



सच कहने की ताकत

# जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र



JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 29 MAY TO 4 JUNE 2020 • VOLUME-38 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

**INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE**

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

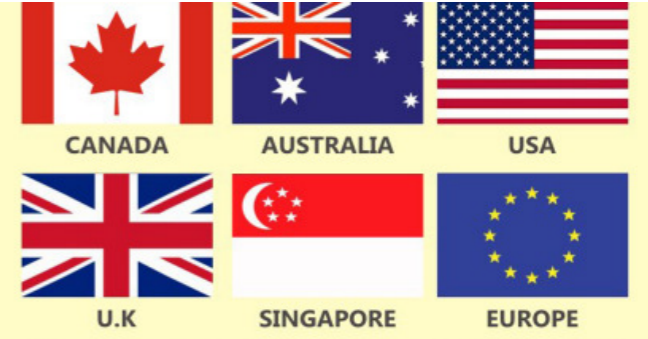
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

## STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

No Filing Charges & \*Pay money after the visa

## IELTS | STUDY ABROAD



## मेयर जगदीश राजा ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को बांटे सेफ्टी उपकरण

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर नगर निगम के मेयर जगदीश राजा द्वारा पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं और पिछले दो महीने से अनेकों बार निगम कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण मुहैया कराये गए। इसी लड़ड़ीवार में आज फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के दफ्तर में मेयर राजा और उनके साथी पार्षदों द्वारा मास्क शील्ड, अलकोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और दस्ताने जैसे सेफ्टी उपकरण बांटे गए और मेयर राजा ने कहा कि आगे भी इन कोरोना वायरस को जो भी जरूरत पड़ेगी वो उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।



# सुखपाल खेहरा सरकार के खिलाफ फिर एक बार गरजे

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

फिल्मों में तो कई हीरो लोगों के रक्षक के किरदार में दिखाए जाते हैं पर पंजाब के दोआबा क्षेत्र का एक तेज तरवार नेता और विधायक सुखपाल खेहरा हकीकत में लोगों के लिए रक्षक के रूप में देखा जाता है। कई मुद्दों पर सरकार के नाक में दम इस नेता द्वारा किया जाता रहा है जब विरोधी दल के नेता के रूप में आम आदमी पार्टी के द्वारा नियुक्त किया। उस समय लोगों का कहना था कि अब पता लगा कि विरोधी दल के नेता का काम क्या होता है। इसी लड़ड़ीवार में जालंधर में आज उनके द्वारा पंजाब में एक बहुचर्चित हत्या कांड जिसमें की पंजाब के एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई और एक पंजाब पुलिस में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा की गयी परन्तु पंजाब सरकार द्वारा उस परिवार के साथ एक बार भी वार्ता लाप नहीं किया गया और न ही कोई मुआवजे का ऐलान किया गया। पुलिस की शोमोलियत ने पुलिस को फिर एक बार इस कोरोना महामारी में बैक फुट पर खड़े कर दिया और इसके खिलाफ शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए देश भगत यादगार हॉल में अपने चंद समर्थकों को कैडल मार्च के लिए एकत्रित



किया परन्तु पुलिस ने उनको और उनके समर्थकों को प्रदर्शन करने से रोका और उनको हिरासत में लेकर डिवीजन नंबर 4 ले जाकर थोड़े समय बाद छोड़ दिया गया परन्तु बहार निकलने के बाद मीडिया से रबूर होते हुए



बयान दिया कि न तोह वोह पहले कभी पुलिस की धकेशाही के खिलाफ पहले भी नहीं कभी घबराये और ना ही अब घबराएंगे और पीड़ित परिवार को हक दिलवाने के बाद ही चुप बैठेंगे।

## न्यूज़

### स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा 29 जून से शुरू

भोपाल, (एजेंसी)। मग के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों की स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक की परीक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होंगी। 29 जून से 31 जुलाई के मध्य में पेपर मॉड पर परीक्षा केंद्रों पर जाकर विद्यार्थियों को परीक्षा देना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा सभी शासकीय, अशासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परीक्षाओं एवं अकादमिक कैलेंडर के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केंद्रों पर सौशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

### छग के पूर्व सीएम जोगी की तबियत फिर नाजुक

रायपुर, (एजेंसी)। छग के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी की स्थिति बुधवार रात फिर हुर हदयथात के बाद नाजुक है। लगभग तीन सप्ताह से वह अस्पताल में भर्ती हैं, और कोमा में हैं। नारायण अस्पताल के निदेशक डा.सुनील खेमका द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सतत कई दिनों से श्री जोगी की स्थिति स्थिर रहने के बाद बुधवार शाम से फिर खराब हो गई और रात्रि में एक बार फिर उन्हें हदयथात हुआ। डाक्टरों ने अथक प्रयास कर और उन्हें सीपीआर दिया जिससे उनकी हृदयगति वापस आई। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार श्री जोगी का इस समय हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और अन्य आइटीएल पैरामीटर नियंत्रण में हैं।

### कोरोना की चपेट में आए संविद पात्रा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्त संविद पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे अस्पताल के आईसीयू-7 में भर्ती हैं। जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इससे पहले सूत्रों के ब्यावसे बताया गया था कि कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देने के बाद भाजपा प्रवक्त को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सूत्र ने कहा था कि भाजपा नेता में कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखाई दिए। पात्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और कई न्यूज चैनल पर भाजपा के चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं।

# राज्यों को 'सुप्रीम' दिशानिर्देश श्रमिकों से नहीं वसूले किराया

## राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी खर्च, खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाए

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को किराया वहन करने और खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई अंतरिम आदेश गुरुवार को जारी किये।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों तथा कुछ हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये। न्यायालय ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनसे न तो रेल का किराया लिया जाएगा, न ही बस भाड़ा।

भारत	कुल मामले	स्वस्थ हुए	संक्रमित	कुल मौत
	1,65,356	70,788	89847	4,710
	7,453	4,050	3,082	321



कोर्ट ने कहा कि इन मजदूरों के किराये पर आने वाला खर्च संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। इतना ही नहीं, विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूरों को संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

### गृह मंत्री ने सीएम से की बात, लॉकडाउन 5 पर मार्ग सुझाव

देश में लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में आगे क्या हो, लॉकडाउन 5 लागू हो या नहीं? अगर हो तो उसकी तारीख कैसी हो? इन सब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्री शाह ने प्रदेशों के सीएम से फोन पर चर्चा की और लॉकडाउन 5 को लेकर उनसे सुझाव मांगे। इससे पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट सचिव की मीटिंग में केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव देने के लिए शनिवार तक का समय दिया है।

### कोरोना वैक्सीन पर अक्टूबर तक मिल सकती है सफलता

स्वास्थ्य व गृह मंत्रालय की पीसी में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना का वैक्सीन बनाने में देश में 30 गुण जुटे हैं, लेकिन यह बहुत जोखिमपूर्ण काम है। इस मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री-क्लीनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। दुनियाभर में वैक्सीन बनाने की चार प्रक्रिया हैं। भारत में इन चारों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। दुनिया में चार तरह के वैक्सीन बन रहे हैं- 1. मरना (Marna) वैक्सीन वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ही लेकर जब आयु इंजेक्ट कर लेते हैं। 2. स्ट्रुक्चर वैक्सीन जो वायरस के कमजोर वर्जन को लेकर बनाया जाता है पर उससे बीमारी नहीं फैलती। 3. किसी और वायरस की बैकबोन में कोरोना के वायरस की प्रोटीन कोडिंग को लगाकर के वैक्सीन बनाया जाता है। 4. वायरस का प्रोटीन तैल में बनाकर उसको किसी दूसरे रटीमूलक के साथ लगाया जाता है।

### भोपाल में 17 नए मरीज संक्रमण से 52 वीं मौत

भोपाल (आरएनएन)। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को 17 नए संक्रमित मिले हैं। यही नहीं, हमीरिया अस्पताल में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इस महिला की हमीरिया अस्पताल में एक दिन पूर्व हुई दिलेवरी के बाद बच्चे की मौत हो गई थी। महिला की हालत गंभीर होने एवं उसकी कमजोरी बढ़ने के चलते दूसरे दिन वह चल बसी। भोपाल जिले में मृतकों आंकड़ा 52 हो गया है। जिले में कुल संक्रमित 1459 हैं विरायत अस्पताल में राजगढ़ जिले के व्यापार तहसील की निवासी संक्रमित रुखसाना बी (55) पति इशक खान की गुरुवार को मौत हो गई है। जिले में किसी दूसरे जिले के संक्रमित मरीजों की यह पहली मौत हुई है।

### इंदौर में 84 नए केस, चार की मौत, 118 डिस्चार्ज, कुल संक्रमित 3,344

इंदौर, (आरएनएन)। गुरुवार रात जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1073 टेस्ट की जाव में 84 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। 964 सैपल की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। वहीं गुरुवार को 583 संक्रमित लिए गए। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,344 हो गई। चार मरीजों की मौत हो गई। कुल मृतक संख्या 126 हो गई है। गुरुवार को 118 डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 1,673 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।

### रेलवे ने 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन तक बढ़ाया, कर्नाटक में 5 राज्यों से आने वाली ट्रेनों पर रोक

रेलवे ने 12 मई से शुरू हुई राजधानी रूट की 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इसके अलावा 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में पारसल और लगेज बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने संक्रमण रोकने एहतियातन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य और राजस्थान से आने वाली ट्रेन और अन्य वाहनों पर रोक लगाई। हालांकि, येंदियुग्णा सरकार ने कहा है कि इन राज्यों से आ रही उड़ानों पर बंधन नहीं होगा।

## प्रदेश में एक जून से प्रारंभ होगी रेल सेवा : डॉ. मिश्रा

### 15 ट्रेनों का रहेगा स्टॉपेज

भोपाल, (एजेंसी)। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि एक जून से मध्यप्रदेश में भी रेल सेवा आरंभ होगी। प्रदेश में 15 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। उक्त ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त रहेंगी। मंत्री डॉ. मिश्रा ने रेल आवागमन संबंधी भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।



रेलवे स्टेशनों पर होगी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं अन्य प्रबंधों के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। जांच में संभावित संक्रमित पाए गए यात्रियों को 14 दिवस के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में रहने से असहमत रहने वाले यात्रियों को उनके स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित निजी होटलों में भी क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन अर्थात् समाप्त होने के उपरांत पुनः जांच की जाएगी एवं रिपोर्ट नैगेटिव पाए जाने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। डीआरएम भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रेनों का स्टॉपेज सागर, विदिशा, गयसेन, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और शाजापुर जिले में होगा।

## एचआरडी मंत्री का लाइव सेशन में बड़ा एलान कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मिलेगा प्रमोशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है।



प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। यानी इन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि फाइनेल इंटर या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, जैसा कि यूजीसी ने घोषणा की है। यदि कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार नहीं होता तो वे परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। वहीं अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इनके प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। यानी इन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने इसे चुनौती को अवसर में बदलने वाला समय बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है और जल्द ही इसे संसद से पास करारक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. निशंक ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 45000 उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की कि कोविड 19 के इस चुनौती भरे समय को हम कैसे बदल सकते हैं।

## कोशियारी ने खर्च में कटौती की सात अहम घोषणाएं कीं

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकट को देखते हुए खर्चों में कटौती करने के लिए सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में पहला राजभवन में अगले आदेश तक स्थाई भर्तियों पर रोक और दूसरी कुलपतियों तथा विभिन्न अधिकारियों के यात्रा करने पर होने वाले खर्च का टालने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक को अनिवार्य बनाना शामिल है। इस के अलावा राज्यपाल ने जिन परियोजनाओं का काम पहले चल रहा है उन्हें पूरा करने की इजाजत दी है लेकिन नये निर्माण या मरम्मत कार्यों की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नई कारों की खरीद को भी टाल दिया गया है।



अतिथियों के सम्मान में आयोजित नहीं होंगे भोज

## रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश पर विदेश मंत्रालय ने कहा सीमा पर तनाव कम करने चीन से वार्ता जारी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत-चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ वार्ता चल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रुख अपनाया है। चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते में रखी गई प्रक्रियाओं का भारतीय सैनिक सख्ती से पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार को भारत-चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। हाल के



संघ संकेत देता है। 5 मई से दोनों देश के बीच तनाव की स्थिति: 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के बाद दोनों सेनाएं उस इलाके में डंटी हुई हैं। जाकारों का कहना है कि चीन के शांति संबंधी बयान को जमीन पर देखना होगा। जहां चीन सीमा संबंधी धारणा को बदलना चाहता है।

दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफ़ी हद तक बढ़ाई है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच दो अलग-अलग, तनावनी की घटनाओं के दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी तनाव बढ़ने और दोनों पक्षों के रुख में कठोरता आने का संकेत देता है।

भारत-चीन के रिश्तों को प्रगाढ़ करने की जरूरत : विडोंग

भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत और चीन के रिश्तों को प्रगाढ़ करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। विडोंग ने आगे कहा कि चीन और भारत कोविड-19 के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पर अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी है।

## रेलवे स्टेशनों पर अभी नहीं मिल पाएगा खाना-पानी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रेलवे भले ही योजना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल और अन्य ट्रेनें चला रहा हो, 1 जून से 100 जोड़ी और ट्रेनें चलाने की योजना हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले वेंडर अभी अपनी दुकानें खोलने को तैयार नहीं हैं।



वेंडर फिलहाल दुकानें खोलने को तैयार नहीं

रेलवे फूड वेंडिंग एसोसिएशन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते अभी वे प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसने रेल अधिकारियों से दुकानें खोलने के लिए दबाव नहीं डालने का आग्रह किया है। 25 मार्च से पूरे देश में लॉक डाउन के चलते रेलवे प्लेटफॉर्म की सभी दुकानें बंद हैं।

दखल



# ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियां

ऑनलाइन शिक्षा व परीक्षा के संबंध में हाल में जिस तरह के फैसले हुए हैं, वे वक्त की मांग तो हैं लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, इसमें संदेह है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों ने अपने यहां न केवल शिक्षण कार्य, बल्कि परीक्षा जैसे काम तक ऑनलाइन शुरू करने का फैसला किया है। इस कवायद से छात्रों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यावहारिक मुश्किलों और तकनीकी संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षण की सुविधाएं सर्वसुलभ नहीं हैं और इसी वजह से छात्रों और शिक्षकों को इसमें तात्कालिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, दूसरी ओर हमारे सामने अब बदलती दुनिया में तकनीक के साथ चलने की चुनौती भी है। आज दुनिया के तमाम शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर हमें उनके साथ दौड़ में शामिल होना है तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सवाल इतना भर है कि भारत जैसे देश में इसे आसानी से कैसे स्वीकार्य बनाया जाए। लोकडउन से जुड़ रही दुनिया में अब ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। कहना न होगा कि जीवन का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संस्कृति में ढलने को मजबूर हो चुका है। इसी क्रम में ऑनलाइन शिक्षा भी एक विकल्प के रूप में सामने आई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूली बच्चे तक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होंगे। लेकिन अब यह हो रहा है, भले अड़चनें कितनी ही क्यों न हों। भारत के शिक्षा जगत की जमीनी हकीकत दुनिया से अलग है। अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों में, जहां हर व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, वहां पर भी शिक्षाविदों के बीच में ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा के बारे में एक राय नहीं है। अमेरिका में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों की सफलता दर प्रत्यक्ष कक्षाओं के छात्रों की तुलना में आठवां हिस्सा ही है। लोकडउन के कारण देश भर में छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। यह स्थिति देश के स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में देखने को मिल रही है। इस तरह की आपात परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालयों में लागू की गई और पाठ्यक्रम को पूरा मान कर ऑनलाइन परीक्षाएं करने की तैयारियां भी चल रही हैं।

हकीकत यह है कि न सिर्फ विभिन्न क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान, बल्कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस दिशा में कदम बढ़ाने को

लेकर दुविधा में हैं। इसका बड़ा कारण है कि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वे अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षण संस्थानों के पास तो फिर संसाधन हो सकते हैं, भले सीमित हों, लेकिन छात्रों का बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। यही वह प्रमुख बिंदु है जो ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा को लेकर सबको चिंतित कर रहा है। छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का प्रतिकूल प्रभाव आगे जाकर रोजगार की तैयारियों पर भी पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों को नजरअंदाज करना इसके लक्ष्य में बड़ी बाधा साबित हो सकता है। छात्रों और शिक्षकों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे तत्काल इस प्रणाली को आत्मसात कर लें और ऑनलाइन एप, ई-रिसोर्स व अन्य ऑनलाइन शिक्षण के तरीकों से सामान्य दिनों की तरह शिक्षण गतिविधियां चलाते रहें। लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या ऐसा संभव हो पाएगा, बड़ा सवाल है।

इस ऑनलाइन कवायद का नतीजा अब तक इस रूप में सामने आया है, जिसमें शिक्षक किसी भी तरह से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने और औपचारिकता में लग गया है व बहुसंख्यक छात्र ऑनलाइन पढ़ाई की समस्याओं से जुड़ रहे हैं। यह एक असाधारण दौर है और ऐसे समय में बेशक नए प्रयोगों की जरूरत है। चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी और विभिन्न विश्वविद्यालयों से लेकर कॉलेज के शिक्षक तक, सभी नए और सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह है छात्र। हमारे विश्वविद्यालयों में विभिन्न पृष्ठभूमियों से छात्र आते हैं। इनमें से बहुत से छात्र पहले से ही जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आदिवासी पृष्ठभूमि या शारीरिक निशकता के आधार पर कई तरह की चुनौतियां झेल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों का है जो मार्च में छुट्टियों में अपने घर चला गया। अपने घरों में इन छात्रों के पास किताबों सहित दूसरी अध्ययन सामग्री नहीं है। ऐसे में छात्रों के सामने सवाल है कि कैसे पढ़ाई करें। छात्रों की यह मुश्किल तकनीकी संसाधनों के अभाव की वजह से है।

छात्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों से आता है जहां इंटरनेट की समस्या है। ऐसे छात्रों की संख्या भी कम नहीं है जिनके पास लैपटॉप जैसी सुविधा नहीं है। स्मार्टफोन के सहारे पढ़ाई संभव नहीं है। इसी तरह निश्चकन छात्रों की विशेष जरूरतों को भी ध्यान देना होगा,

जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वाइफाई तकनीक तक पहुंच नहीं है और जो शिक्षण संस्थानों में मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों और सुविधाओं पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। यह विडंबना ही है कि ऑनलाइन शिक्षण का यह संकट विश्वविद्यालय व्यवस्था के ह्रासिये पर मौजूद दूरस्थ माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा में लंबे समय से चल रहे संकट का हल्का रूप है। पिछले दशक में विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लें। यहां हर साल स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में एक लाख से ज्यादा छात्र दाखिला लेते हैं। ज्ञात हो कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में ज्यादातर छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं।

नियमित कॉलेजों में सीटों की कमी के कारण या आर्थिक दिक्कतों के कारण दाखिला न ले पाने वाले छात्र बेहद खराब ढंग से चल रही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां बिना कक्षाओं के ही पाठ्यक्रम पूरा करना व गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का अभाव एक आम बात है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की पढ़ने की क्षमताएं भी भिन्न होती हैं। ऐसे में उनकी जरूरतों को सिर्फ प्रत्यक्ष कक्षाओं में ही बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। अलग छात्रों और समूहों के साथ मिलकर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है। इसके विपरीत, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का साग बोझ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीक और गैजेटों पर निर्भर हो जाता है और इसका सबसे घातक नतीजा यह होता है कि ज्ञान अर्जन एक एकांगी रूप ले लेता है।

बेहतर हो कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए मौजूदा सत्र को थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ताकि स्थिति ठीक होने पर एक निश्चित समय-सीमा के लिए उनके लिए कक्षाएं और पीसीपी (पर्सनल कौंटेंट प्रोग्राम) के सत्र आयोजित किए जा सकें। इसके बाद ही परीक्षाओं के लिए या तो अतिरिक्त अतिरिक्त परीक्षण के तरीकों को अपनाया जा सकता है या बाढ़ परीक्षा की योजना बनाई जा सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षण संस्थानों में आए संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसे उपायों पर अमल करें जिनमें सभी के हितों का समावेश हो।

अलग-अलग छात्रों और समूहों के साथ मिलकर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है। इसके विपरीत, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का सारा बोझ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीक और गैजेटों पर निर्भर हो जाता है और इसका सबसे घातक नतीजा यह होता है कि ज्ञान अर्जन एकांगी रूप ले लेता है।

## विचार

### पाक की बड़ी साजिश फेल

आतंकी और हिज्बुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर में नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है और पुलवामा पार्ट-2 की घटना उसी की ओर इशारा कर रही है। मगर अब वह इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा।



सुरक्षा बलों की मुस्तेदी ने गुरुवार को पुलवामा पार्ट 2 साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों का प्लान 40 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों वाले कार बम से सुरक्षा बलों को दहलाने का था लेकिन अलर्ट सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस खतरनाक आतंकी साजिश को 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की तर्ज पर प्लान किया गया था। उस आतंकी हमले को यादकर आज भी दिल दहल जाता है। जम्मू से 78 गाड़ियों के काफिले के साथ 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर सवा 3 बजे अचानक विस्फोटकों से लदी एक कार काफिले में शामिल एक बस से टकराई। तेज धमाके के साथ बस और कार के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे का इलाका उसकी आवाज से दहल गया। यह आत्मघाती हमला था जिसे अंजाम दिया था जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी आदिल अहमद डार।

सीआरपीएफ के 76वें बटालियन के 40 जवान शहीद हो गए। कई अन्य घायल हुए। पाक की शह पर हुए इस दिल दहला देने वाले कायराना हमले से पूरा देश तब तक उबलता रहा जब तक बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने शहीदों की शहादत का बदला नहीं ले लिया। हमले के 12वें दिन 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। जम्मू-कश्मीर पर दुनियाभर में दुष्प्रचार के बाद भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इस मुद्दे पर किसी देश का साथ नहीं मिला। हताश-परेशान इमरान खान जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 से बोखलाए हुए थे लेकिन उनकी कोई भी नापाक चाल घाटी में सफल नहीं हुई। वहीं, सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी ने पाक प्रयोजित आतंकवाद पर नकेल कस रखी है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना घाटी में आतंकियों के जरिए भारत को परेशान करने की साजिश में जुटे हुए हैं। भारत के मुस्तेद सुरक्षाबलों ने न केवल आज पुलवामा-2 को टाल दिया बल्कि पड़ोसी देश को चेतावनी भी दे दी कि उनसे नापाक मंसूबे भारत कामयाब नहीं होने देंगे।

सीमा पर भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तानी सेना कश्मीर में मौजूद स्थानीय व विदेशी आतंकियों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलवामा पार्ट-2 की कोशिश को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आतंकियों से पकड़ी गई कार में करीब 40 किलो बूझधू थी। इतना बड़े पैमाने पर विस्फोटक बिना पाक की मदद के उपलब्ध नहीं हो सकता है। साफ है कि पाक भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी लगातार साजिश रच रहा है। कश्मीर के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद पाक कश्मीर में नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है और मौजूदा घटना उसी की ओर इशारा कर रही है।

# दूध उत्पादकों की चुनौतियां

दुनिया में दूध उत्पादन में अक्वल होने के साथ भारत दूध की सबसे ज्यादा खपत में भी पहले स्थान पर है। बावजूद इसके पशु पालकों की गिनती देश की आर्थिकी में नहीं की जाती है। इन्हें और मछुआरों को सामान्य किसानों में ही शामिल कर लिया जाता है। लेकिन हाल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में दूध उत्पादकों और पशु पालकों की सुध ली गई है। दो लाख करोड़ रुपए के कर्ज पशु पालकों को दिए जाएंगे। हालांकि मवेशियों और इनके पालकों का अगर ठीक से संरक्षण करना है तो वन संरक्षण अधिनियम में सुधार कर पशुओं को आर्थिक वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में घास चरने की अनुमति देनी होगी। इससे एक साथ दो फायदे होंगे, एक तो ये जंगली घास, फल-फूल और पत्तियां खाएंगे तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, नतीजतन देश की आबादी को पौष्टिक आहार मिलेगा। इससे बीमारियां भी कम होंगी। दूसरा लाभ यह कि जो पशुधन दुर्घटनाओं में रोजाना बड़ी संख्या में मर रहा है, उसे जीवनदान मिल जाएगा।



देश के प्रत्येक नार्थिक को औसतन दो सौ नब्बे ग्राम दूध रोजाना मिलता है। इस हिस्से से कुल खपत प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर दूध की हो रही है। जबकि शुद्ध दूध का उत्पादन करीब 15 करोड़ लीटर ही है। दूध की लगातार बढ़ रही मांग से मिलावटी दूध का कारोबार गांव-गांव फैलता जा रहा है। दूध की कमी की पूर्ति सिंथेटिक दूध बना कर और पानी मिला कर की जाती है। यूरिया से भी दूध बनाया जा रहा है। बहलाल, मिलावटी दूध के दुष्परिणाम जो भी हों, इस असली-नकली दूध का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान एक लाख 15 हजार 970 करोड़ रुपए का है। दाल-चावल की खपत से कहीं ज्यादा दूध और उसके सह-उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। साल 2018 में देश में दूध का उत्पादन 6.3 फीसद बढ़ा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय वृद्धि दर 2.2 फीसद रही है। दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें इस व्यापार को हड़पने में लगी हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार करने वाली फ्रांस की कंपनी लेकटेल् है, जिसने भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद की तिरुमाला दूध डेयरी को 1750 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डेयरी को चार किसानों ने मिल कर बनाया था। भारत की तेल कंपनी ऑयल इंडिया भी अब दूध कारोबार में प्रवेश कर रही है, क्योंकि दूध का कारोबार 16 फीसद सालाना की दर से बढ़ रहा है। बिना किसी सस्कारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसद कारोबार असंगठित क्षेत्र संभाल रहा है। इस

यदि अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों के निर्यात की छूट दे दी गई तो भारतीय डेयरी उत्पादक अमेरिकी किसानों से किसी भी स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। नतीजतन डेयरी उत्पाद से जुड़े जो 12 करोड़ लघु और सीमांत भारतीय किसान दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाएंगे।

कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, माया आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसद कारोबार संगठित क्षेत्र जैसे डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में छिपाने व हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं।

14 राज्यों की अपनी दूध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसद हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे सात करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सीधे शहरी और कस्बाई ग्राहकों तक भी दूध बेचने का काम करते हैं। जीवनदायी दूध में मिलावट कोई नहीं बात नहीं है। हमारी ज्ञान परंपरा

में शुद्ध दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला कर ही पीने का प्रचलन है, जिससे दूध को पचाने में आसानी हो। लेकिन दूध में मिलाए जाने वाले जिन हानिकारक तत्वों की जानकारी सामने आई है, वह हैरान करने वाली है। बाजार में मिलने वाला 68 फीसद दूध मिलावटी है जो यूरिया, कार्बोनाट सोड, डिटेजेंट पाउडर, कृत्रिम चिकनाई, सफेद रंग और पेंट तक मिला कर बनाया जा रहा है। तय है, इस तरह की अखाद्य वस्तुएं जब जीवनदायी दूध में मिलाई जाएंगी तो देश का युवा होता बचपन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब विषैले तत्वों को मिला कर दूध बेचा जाएगा, तब वह भयंकर बीमारियों का सबब तो बनेगा ही।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2011 में दूध की गुणवत्ता नापने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। इस मकसद की पूर्ति के लिए एक हजार 791 नमूने देशभर से इकट्ठे किए गए थे। इनमें सभी 28 राज्य और पांचों केंद्रशासित

प्रदेश शामिल थे। लुद्दाख उस समय स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश न होते हुए जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा था। तब तेलंगाना अस्तित्व में नहीं आया था, इसलिए जम्मू की संख्या 28 ही थी। इन नमूनों में से 68 फीसद नमूने एफएसएसआई के मानकों पर खरे नहीं उतरें। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड और दमन-दीप में हालात कुछ ज्यादा ही बदतर हैं। इस सर्वे से यह सचचाई भी सामने आई है कि हम सबसे ज्यादा दूध इसलिए उत्पादित कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मिलावटी दूध उत्पादन की मात्रा भी जुड़ी हुई है। इस व्यवसाय पर अमेरिका समेत अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका की इस मंशा को समझने के लिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाले आयात-निर्यात को समझना होगा।

2018 में दोनों देशों के बीच 143 अरब डॉलर यानी दस लाख करोड़ का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका को 25 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। इसकी भरपाई वह दुग्ध और पौल्ट्री उत्पादों का भारत में निर्यात करके करना चाहता है। इस नाते उसकी कोशिश है कि इन वस्तुओं व अन्य कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क घटाने के साथ उन दुग्ध उत्पादों को बेचने की छूट भी दे, जो पशुओं को मांस खिला कर तैयार किए जाते हैं। दरअसल अमेरिका में इस समय दुग्ध-उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी लोगों में दूध की जगह अन्य तरल-पेय पीने का चलन बढ़ने से दूध की खपत घट गई है। इस कारण दूध किसान आर्थिक बदहाली के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका अपने किसानों को प्रति किसान साठ हजार डॉलर से ज्यादा (करीब 44 लाख रुपए) सालाना की सब्सिडी देता है। इसके उलट भारत में सब मदों में मिलाकर किसान को 16 हजार रुपए की सालाना की मदद दी जाती है।

भारतीय नियमों के अनुसार यदि भारत किसी देश से दूध उत्पादों का आयात करता है तो उसके निर्यातों को यह प्रमाणित करना होगा कि जिन मवेशियों के उत्पाद भेजे जा रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे जानवर के आंतरिक अंगों एवं मांस तो नहीं खिलाए जाते हैं। यह नियम 2003 से लागू है। हालांकि ऑनलाइन व्यापार के जरिए मांस युक्त आहार बिकता है। हमारे यहां गाय-भैंस भले ही कूड़े-कचरे में मूंह मारती फिरती हों, लेकिन दुग्धरू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई नहीं सोच सकता।

## ट्विटर

पुलवामा जैसी घटना दोहराने की साजिश रच रहे पाक को यह नहीं पता कि इस बार वह अपने मंसूबे में सफल हुआ तो पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा।

**मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ**

पाकिस्तान की कोई भी चाल भारतीय सेना कामयाब नहीं होने देगी। आतंकियों के सहारे वह जो कुचक रच रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब हर बार दिया जाएगा।

**मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख**

## सत्यार्थ

एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। उसको एक नौकर की जरूरत थी। जब नौकर रखना था, तो परीक्षण जरूरी था। तब उसने अनेक लोगों को बुलाया, क्योंकि नौकर बहुत काम करने वाला होता है, लेकिन आदमी बहुत खतरनाक भी होता है। कोई खतरनाक आदमी न आ जाए, इसके लिए ही परीक्षण जरूरी था। बादशाह को एक युक्ति सूझी। उसने उपस्थित लोगों में से तीन को सामने खड़ा करके कहा-बताओ, इतनेफाक से मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए, तो

तुम क्या करोगे? पहला तुरंत बोल उठा, हुजूर! आपकी दाढ़ी की आग तुरंत बुझा दूंगा। अपनी दाढ़ी की आग की चिंता नहीं करूंगा। दूसरा बोला कि जहांपनाह! पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और फिर आपकी दाढ़ी की चिंता करूंगा। तीसरा बोला-हुजूर! एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। बादशाह ने तीनों व्यक्तियों के उत्तर सुनकर कहा-पहला आदमी अत्यंत बुद्धिमान था। दूसरा आदमी भी बुद्धिमान था। तीसरा आदमी अत्यंत अंधा था।

दुनिया में ऐसा कोई नहीं, जो कठिन समय आने

## सही आदमी का चयन

पर अपनी बात न सोचकर दूसरे की सोचता हो, अपनी नहीं, बल्कि दूसरे की चिंता करे। इसलिए यह आदमी या तो झूठा है या अज्ञानी। दोनों ही स्थितियों में वह खने योग्य नहीं है। दूसरा स्वार्थी है। स्वार्थी आदमी किसी का भला नहीं करता। वह सदा अपनी बात सोचता है, अपना ही भला करता है। वह आदमी भी खतरनाक होता है। आखिरी में बादशाह ने कहा-तीसरा आदमी न अत्यंत अंधा है और न स्वार्थी। वह व्यवहार के धरातल पर ही जितता है। इस प्रकार, बादशाह ने सही व्यक्ति का चयन कर उस तीसरे व्यक्ति को नौकरी दे दी और बाकी दोनों को वहां से खाना कर दिया।



## पंजाब सरकार द्वारा विद्यार्थियों को किताबों के वितरण का लेखा-जोखा रखने के लिए पुस्तकों की एंटी अनिवार्य की

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को किताबें बाँटने की प्रक्रिया को यकीनी बनाने और इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए बॉटी जा रही किताबों का लेखा-जोखा रखने के लिए पुस्तकों की एंटी अनिवार्य कर दिया है। यह एंटी समूह स्कूल प्रमुख अपने स्कूल की लॉग इन आई.डी. पर करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य कार्यालय द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार करके इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल और स्पष्ट बना दिया गया है और इसका लिंक ई-पंजाब स्कूल पोर्टल पर दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार मुख्य कार्यालय द्वारा इस मौके पर निरीक्षण टीमों भेज कर किताबों के वितरण संबंधी जानकारी हासिल की जाएगी। जिससे कोई भी विद्यार्थी किताबें प्राप्त करने से वंचित न रहे। प्रवक्ता के अनुसार किताबों के वितरण को यकीनी बनाने के लिए सचिव स्कूल शिक्षा / डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा द्वारा स्वयं उप-जिला शिक्षा अधिकारियों, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पब्लिकेशन शाखा और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसों के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान आए सुझावों के मद्देनजर किताबों की एंटी करने की प्रक्रिया को और सरल एवं स्पष्ट किया गया है।

## ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टैस्ट देने की प्रक्रिया 1 जून से होगी शुरु-स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने नागरिकों को रैगुलर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टैस्ट देने सम्बन्धी समय और तारीख को प्री-बुकिंग करवाने की सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली को शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टैस्ट के इस मंतव्य के लिए ड्राइविंग टैक 1 जून, 2020 से कार्यशील हो जाएंगे। यह खुलासा आज यहाँ जारी प्रेस बयान में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अब कोई व्यक्ति सिर्फ प्री-बुकिंग के अनुसार ही टैस्ट दे सकेगा और अधिकारियों की अपने विवेक के अनुसार टैस्ट आयोजित कराने सम्बन्धी शक्तियाँ वापस ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बुक किए गए समय पर उपस्थित नहीं होता तो टैस्ट सम्बन्धी समय दोबारा बुक करवाना होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि अपनी बारी से पहले टैस्ट देना या बिना बुकिंग करवाए टैस्ट देना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के साथ होने वाले शोषण को भी रोका जा सकेगा। डॉ. अमरपाल सिंह ने आगे कहा कि एक और विशेषता जिसे शुरू किया गया है, वह है कि लाइसेंस के टैस्ट का नतीजा और लाइसेंस बनाने

### ड्राइविंग टैस्ट देने संबंधी तारीख और समय लेने के लिए पहले करवानी होगी बुकिंग

सम्बन्धी प्रक्रिया एक ही दिन के अंदर शुरू की जाएगी। हरेक टैक पर उपलब्ध स्लॉट्स की संख्या 40 तक सीमित कर दी गई है, जिससे कोविड-19 के मद्देनजर शारीरिक दूरी को बरकरार रखा जा सके। जनता की सुविधा के लिए अब व्यक्ति अपनी परीक्षा देने के लिए जिले में किसी भी टैक की चयन कर सकेगा, जबकि पहले सिर्फ एक ही टैस्ट टैक चुनना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि लर्नर लाइसेंस संबंधी पहले वाली विधि ही जारी रहेगी और जनता यह लाइसेंस 500 से अधिक सेवा केंद्रों और आरटीए / एसडीएम कार्यालयों से प्राप्त करने के योग्य होंगे। "मोटर व्हीकल एक्ट 1988के अंतर्गत जारी किए गए सभी दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी, जिसमें फरवरी 2020 के बाद खत्म हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं।" स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि टैस्ट देने सम्बन्धी प्री-बुकिंग के लिए कोई भी वेबसाइट [www.sarathi.parivahan.gov.in](http://www.sarathi.parivahan.gov.in) पर लॉगइन कर सकता है।

## वस्तुओं के असल भाव से अधिक भाव वसूल करने वालों को किया गया 11,02,000 रूपए का जुर्माना-आशु

चंडीगढ़/ब्यूरो

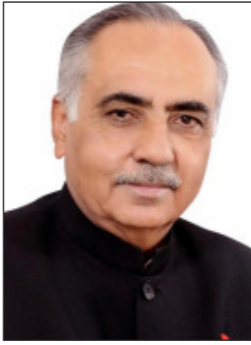
राज्य के लोगों को वस्तुओं के असल भाव से अधिक कीमत वसूलने से बचाने के मकसद से राज्य भर में 1325 दुकानों और कैमिस्ट दुकानों पर छापे मारे गए, जिनमें से 176 व्यापारिक संस्थाएं असल कीमत से अधिक कीमत वसूल कर रहे थे, जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनको 11,02,000 के जुर्माने किए गए हैं। यह जानकारी आज यहाँ पंजाब के उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने दी। उन्होंने बताया कि वस्तुओं की असल कीमत से अधिक कीमत वसूलने सम्बन्धी उनके विभाग को 7 शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्यवाही करते हुए राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान 186 दुकानदारों पर तय कीमत से अधिक कीमत वसूल करने के मामले में पी.सी.आर. एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अधीन मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 176 दुकानदारों का पी.सी.आर. एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के तहत मामले दर्ज करके जुर्माने किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों के अनुसार विभाग राज्य में जरूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. या उससे कम होने को यकीनी बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है।

## पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने सामाजिक सुरक्षा विभाग में सुपरवाइजर्स के 94 पदों के नतीजों का क्रिया एलान

चंडीगढ़ / एस.एस.ए. नगर / ब्यूरो

तालाबन्दी के कारण और विभिन्न विभागों के कामकाज में आई आम गिरावट के बावजूद, पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पीएसएसएसीबी), पंजाब सरकार के विभागों के विभिन्न पदों का नतीजा घोषित करके बहुत से परिवारों को उम्मीद और खुशी दे रहा है।

श्री रमन बहल की अध्यक्षता अधीन 28मई को हुई एक विशेष मीटिंग में पी.एस.एस.ए.सी.बी. के सदस्यों ने 10% के सामाजिक सुरक्षा विभाग में सुपरवाइजर्स के 94 पदों का नतीजा घोषित किया। श्री बहल ने बताया कि इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के नाम सम्बन्धी सिफारिशें सम्बन्धित विभाग को भेजी जा रही हैं। मीटिंग में जेल विभाग में वीडियो कांफ्रेंस संचालकों के 06 पदों का नतीजा भी घोषित किया गया और



सम्बन्धित विभाग को शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों से जरूरी दस्तावेज हासिल करने की मंजूरी दे दी गई। जिक्रयोग्य है कि इस महीने के शुरू में बोर्ड ने फूड सेफ्टी अफसरों के 25 पदों का नतीजा घोषित किया था। श्री बहल ने कहा, "नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता के प्रति अडिग खड़े होकर, पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जल्द ही निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रक्रिया के द्वारा जरूरी पदों पर भर्ती करके इस पहलकदमी का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड के सदस्यों ने विभिन्न विभागों में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 440 और सहायक जेल सुपरिटेण्डेंट के 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस सम्बन्धी उम्मीदवारों से आवेदन मांगने के लिए एक विज्ञापन जल्द ही जारी

### विभिन्न विभागों में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 440 और सहायक जेल सुपरिटेण्डेंट के 35 पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी-रमन बहल

किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी ढंग से अपेक्षित लिखित परीक्षा करवाने के बाद योग्य उम्मीदवारों की चयन मेरिट के आधार पर की जाएगी। मीटिंग में बोर्ड के सदस्य जसपाल सिंह दिब्रॉ, कुलदीप सिंह काहलॉ, रजनीश सहोता, समशद अली, डोमिला बांसल, भूपिन्दर पाल सिंह, रविन्दरपाल सिंह, अमरजीत सिंह वालिया, हरप्रताप सिंह सिद्धू और अलटा आहलूवालीया शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के अनुसार शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की गई।

## आईसीआईसीआई बैंक वरिष्ठों को देगा अधिक ब्याज

मुंबई/ब्यूरो

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर उंचे ब्याज की पेशकश की है। बैंक ने कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 0.80 प्रतिशत बढ़ी दर से ब्याज देगा। अभी तक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जमा पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देता रहा है। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के साथ ही ब्याज दरों में बड़ी गिरावट आई है। इसके मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक चुजुर्गों को अधिक ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बयान में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को पांच से दस साल की दो करोड़ रूपए तक की जमा पर 6.55 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। यह उत्पाद सिर्फ 30 सितंबर तक उपलब्ध होगा। बैंक के देवदारी सहायक के प्रमुख प्रणव मिश्रा ने कहा, हम जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के एक बड़े वर्ग के लिए एफडी पर मिलने वाला ब्याज उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है।

## न्यूज

### बाबरी मस्जिद मामले में सीबीआई कोर्ट चार जून से दर्ज करेगी बयान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत चार जून से भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 32 आरोपियों के बयान दर्ज करेगी। बयान को कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आठ मई को आदेश जारी करते हुए 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने को कहा था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विपय कटियार, साध्वी ऋतभरा, साक्षी महाराज और रामविलास देवदती शामिल हैं। ज्ञात हो कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। इसी मामले में ये सभी आरोपी हैं। मामले में सीबीआई ने 49 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दखिल की थी, जिसमें से 17 अभियुक्तों को मौत हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिधल, विष्णु हरि डालमिया की सुनवाई के दौरान मौत हो जाने के बाद कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

### मंगला मिश्रा राज्यसभा उप-चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

भोपाल, (एजेंसी)। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक मंगला मिश्रा को मध्यप्रदेश में राज्यसभा उप-चुनाव 2020 कोविड 19 के लिए जनसंपर्क की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खांडे ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आयुक्त डॉ. सुदाम खांडे ने उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय व मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है।

### पायलट आधार पर 10 उप कोषालय को किया जिला कोषालयों में समाहित

भोपाल, (एजेंसी)। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के बाद 93 उप कोषालयों में आहरण-संवितरण अधिकारियों की संख्या पांच या कम रही गयी है। आर्किटेक्चर/आईएस में सभी डीडीओ द्वारा शत-प्रतिशत देयक ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही ई-स्टामिपिंग व्यवस्था शुरू होने से सी रूपये से अधिक राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का प्रदान भी कोषालय से बंद है। समस्त कोषालय व्यवहार के ऑनलाइन होने से उप कोषालयों के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पायलट आधार पर 10 उप कोषालयों को संवित्तित जिला कोषालयों में समाहित करने के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इनमें स्वीकृत सहायक ग्रेड-दो के पद तथा भूचय के पदों पर कार्यरत कार्यालयों को संवित्तित जिला कोषालय की स्थापना में मदद स्थिति दिया गया है। साथ ही स्ट्रॉग रूम में रखी सामग्री भी जिला कोषालय के स्ट्रॉग रूम में संरक्षित रखी जाने को आदेशित किया गया है। शासन ने इस संबंध में की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए आयुक्त, कोष एवं लेखा को अधिकृत किया है। पायलट आधार पर शाहपुर, तेंदुखेडा, सेगांव, नैनपुर, पयई, सैलाना, रामपुर-बधोलान, चित्तौरी, नामदा तथा ग्यारसपुर उप कोषालयों को संवित्तित जिला कोषालयों में समाहित किया जा रहा है।

### भाजपा नेताओं ने वीर सावरकर की जयंती पर अर्पित श्रद्धासुमन

भोपाल, (एजेंसी)। प्रखर राष्ट्रवादी और समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर का उनकी जयंती पर गुरुवार को मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं ने स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में कहा कि भारतीय के समुद्र स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। उन्होंने देश के सबसे संवेक श्री सावरकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित है। राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट में लिखा, विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर कोटिश्री: वंदन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट में कहा, मां भारती के वीर सपुत्र, प्रखर राष्ट्रवादी नेता एवं समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की जी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भागत और अन्य पार्टी नेताओं ने भी श्री सावरकर का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया है।

## Stay Home Stay Safe

### घरेलू यात्री



देश में घरेलू यात्री विमान सेवा की शुरुआत के बाद गुरुवार को मुंबई से पटना के जय प्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे यात्री शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए।

### प्रवासी मजदूर



मुंबई से प्रवासी श्रमिकों का एक दल गुरुवार को विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा।

### केंद्रीय मंत्री तोमर ने की टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की समीक्षा

# टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन से जल्द आएंगे स्प्रेयर

### निपटने के लिए यह भी तैयारी

- दुर्गम क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग शीघ्र
- स्प्रे के लिए हेलीकाप्टरों की सेवाएं लेने की तैयारी, राज्यों को एडवायजरी भी की जारी
- क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित, विशेष दलों के साथ अतिरिक्त कर्मचारी तैनात
- कृषि मंत्रालय ने राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी, समस्या से मिलकर के निपट रहे



नई दिल्ली ■ एजेंसी

कुछ राज्यों में सक्रिय टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्रवाई की गुरुवार को विभागीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुनः समीक्षा की। श्री तोमर ने कहा कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है। राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों को एडवायजरी जारी की जा चुकी है। ब्रिटेन से अतिरिक्त स्प्रेयर 15 दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। इनका आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। 45 और स्प्रेयर भी अगले एक-डेड महीने में खरीद लिए जाएंगे। लंबे पैड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग शीघ्र किया जाएगा। वहीं स्प्रे के लिए हेलीकाप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी है। क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती करते हुए उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सभी स्थानों पर किसानों की मदद से नियंत्रण दल तत्परता से कार्रवाई में जुटे हुए हैं। श्री तोमर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्यों को संसाधनों के अलावा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सभी जागरूक किसानों तथा राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या से निपटा जा रहा है।

### मध्यप्रदेश, राजस्थान, यूपी और पंजाब में किया नियंत्रित

अब तक मध्यप्रदेश के मंडसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, आगर मालवा, छतरपुर, सतना व ग्वालियर। राजस्थान के जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोंही, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, वित्तोडगढ़, देसा, चुरू, सीकर, झालावाड़, जयपुर, करौली एवं हनुमानगढ़, गुजरात के बनसकांठा और कच्छ। उत्तरप्रदेश में झांसी और पंजाब के फाजिल्का जिले में 334 स्थानों पर 50,468 हेक्टेयर क्षेत्र में हीपर और गुलाबी झुंडों को नियंत्रित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के दौसा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, मध्यप्रदेश के मुरना और अग्र के झांसी में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं।

### ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ई-टैंडर आमंत्रित

टिड्डी नियंत्रण कार्यालयों में 21 माइक्रोनेर और 26 उल्ट्रास्ट (47 स्प्रे उपकरण) हैं, जिनका उपयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 60 स्प्रेयर के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है जिनकी आपूर्ति यूके स्थित कंपनी द्वारा की जाएगी। जून में दो बार में 35 और जुलाई में 25 की आपूर्ति हो जाएगी। लंबे पैड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव हेतु ई-टैंडर आमंत्रित किया गया है जल्द ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार 55 वाहनों की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। स्प्रे के लिए हेलीकाप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी है।

## हर जरूरतमंद के खाते में डाले जाएं 10 हजार रुपए

### ताकि परिवार के लिए कर सकें रोजी-रोटी का इंतजाम

लखनऊ, (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित जरूरतमंदों के बैंक खातों में सरकार को दस हजार रुपए अविलंब डालने चाहिए, जबकि अगले छह महीने तक उन्हें साढ़े सात हजार रुपए की आर्थिक मदद मिले ताकि वे मुश्किल वक्त से उबर कर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें।



### यह समय है सहयोग करने का

श्रीमती वाड्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को देखिए, वहां महामारी का भयानक रूप है। वहां की सरकार लड़ रही है, सहयोग देने की बजाय आप वहां की सरकार को गिराना चाह रहे हैं। उसे अस्थिर करना चाहते हैं। मैं खासतौर पर आपको कहना चाहती हूँ कि यह सहयोग करने का समय है। हम सबके ऊपर इस देश की जनता का कर्ज है। आप ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। हर सुख दुख में जनता ने साथ दिया है। आपकी विजय में जय-जयकार किया। हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहें। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में एक-एक भारतवासी साथ खड़ा होना है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जो सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं।

फेसबुक लाइव पर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उन लोगों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं जो लॉकडाउन और कोरोना महामारी के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम यह काम इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बात सुने। 10 हजार रुपए हर जरूरतमंद के अकाउंट में डाला जाए यह मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि अगले 6 महीने तक प्रतिमाह 7500 रुपये जरूरतमंद लोगों के खाते में डाला जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच चुके हैं उनके लिए मनरेगा के कार्य दिवस 100 से 200 दिन तक बढ़ाया जाए। जो लोग लॉक डाउन से जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे उद्योग वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं। उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करें उनको एक आर्थिक पैकेज दे। उनके ऊपर कर्ज ना हो उनके हाथ में पैसा आए ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका गुजारा चल सके। महासचिव ने कहा कि देखिए, मैं आपसे एक खास आग्रह करना चाहती हूँ। सभी राजनैतिक पार्टियों से खास करके भाजपा से कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। यह वक्त पूरे देश को इकट्ठा होने का है। सभी पार्टी के राजनेताओं को वैचारिक मतभेदों को भुलाकर हम सबको सबकी मदद करना है। जब यूपी में आपने हमारी 1000 बसों को नकार दिया।